आकाशवाणी केन्द्र शिमला

02.06.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- पुलिस विभाग में अधिकारी स्तर के पद घटाने और निचले स्तर के कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाएगी राज्य सरकार।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने जनगणना 2027 में सही जानकारी देने का लोगों से किया आग्रह।
- राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय एकता व सांस्कृतिक तालमेल बढ़ाने पर दिया बल।
- राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय लोगों को नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति देने का राज्यपाल से किया आग्रह।
- विकसित भारत वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम 6 जून से काजा में होगा शुरू–विभिन्न राज्यों के युवा स्पिति घाटी के गांवों की संस्कृति से होंगे रूबरू।

सीएम

राज्य सरकार प्रदेश में आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के पद घटाने के बाद अब पुलिस के आला अधिकारियों के पद कम करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य में एक ही काम होने पर भी अलग–अलग पद बनाए गए हैं जिनकी ज़रूरत कम है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उच्च अधिकारियों के पद कम किए जाएं और निचले स्तर पर कर्मियों की भर्ती बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा मे कदम उठाए जाएंगे और सभी फैसले मिल बैठकर ही लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री

इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज शिमला में जनगणना के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में भाग लिया और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को जनगणना के दौरान सही जानकारी देने का आग्रह किया है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और प्रदेश की जनगणना संचालन निदेशक दीपशिखा शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

सुक्खू

इस बीच प्रदेश पुलिस में कार्यरत पूर्व सैनिकों ने मानद नियुक्ति प्रदान करने के लिए आज शिमला स्थित ओक ओवर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए पात्रता सेवा अवधि में आवश्यक छूट देने का निर्णय लिया ताकि उन्हें मानद हैड कांस्टेबल और मानद ए.एस.आई के रूप में नियुक्ति का अवसर मिल सके।

राज्यपाल

एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आज लोकभवन शिमला में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रव्यापी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने और विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। राज्यपाल ने समाज के सभी वर्गों में एकता, सद्भाव, पारंपरिक सम्मान और राष्ट्र गौरव का संदेश निरंतर प्रसारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने समारोह में मौजूद तेलंगाना के नागरिकों को सम्मानित भी किया।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल से जनजातीय क्षेत्र में लोगों को नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि नौतोड़ वन भूमि की स्वीकृति संविधान के शेड्युल 5 के अंतर्गत राज्यपाल के पास निहित है। जगत सिंह नेगी ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 को हटाने का अनुरोध भी किया ताकि प्रदेश के जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों की युवा पीढ़ी को नौतोड़ का लाभ मिल सके। राज्यपाल ने इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की और जल्द उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

विक्रमादित्य

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का नेटवर्क बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। वे आज सोलन जिला के कसौली उपमंडल में काणो के समीप धर्मपुर–सुबाथु–कठनी मार्ग के कार्य का निरीक्षण करने के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन 13 किलोमीटर लम्बे इस मार्ग के लिए करीब 19 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस सड़क का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गड़खल–कसौली को जोड़ने वाले फ्लाईओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया।

वाइब्रेंट विलेज

जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में 6 जून से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से युवा भाग लेंगे। इस दौरान युवाओं को स्पीति घाटी के 10 चयनित गांवों में स्थानीय परंपराओं व संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा।

वकील विरोध

प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने छोटा शिमला से हाईकोर्ट प्रतिबंधित सड़क मार्ग पर अपने वाहनों की आवाजाही पर लागाई जा रही रोक का विरोध जताया है। अधिवक्ताओं ने आज मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर के बाहर प्रदर्शन किया और

उसके बाद सचिवालय का घेराव कर फैसले का वापिस लेने की मांग की। तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के साथ अधिवक्ताओं की वार्ता हुई जिसमें समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन करने पर सहमति बनी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस उनकी गाड़ियों को रास्ते में रोक रही हैं, जिससे उन्हें समय पर अदालत पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।